

(iii) Notification G. S. R. No. 1262, dated the 19th November, 1974, publishing the Indian Forest Service (Pay) Third Amendment Rules, 1974.

[Placed in Library. See No. LT-8725/74 for (i) to (iii)]

Reports of the Comptroller and Auditor General of India (1970-71) on Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited and Hindustan Antibiotics Limited

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. P. SHARMA) : Sir, on behalf of the Dy. Minister of Finance, Shrimati Sushila Rohatgi, I beg to lay on the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution, a copy each (in Hindi) of the following Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1970-71 :

(i) Union Government (Commercial) Part X—Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited.

(ii) Union Government (Commercial) Part XI—Hindustan Antibiotics Limited.

[Placed in Library. See No. LT-8732/74]

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported crisis in Bhilai Steel Plant due to dwindling stocks of coking coal

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान) : श्रीमन्, मैं आपकी याज्ञा में इस्पात और खान मन्त्री का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाता हूँ कि भिलाई स्टील प्लांट के मामले संकट पैदा हो गया है क्योंकि उसके स्टॉक में केवल चार दिन का कोक का कोयला शेष रह गया है।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUKHDEV PRASAD) : Sir, in the first quarter of this financial year, . . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : संत्री जी हिन्दी जानते हैं, हिन्दी में जवाब होना चाहिए।

श्री रबी राय (उड़ीसा) : माननीय मंत्री महोदय की मातृभाषा हिन्दी है, फिर हिन्दी में क्यों नहीं बोलते ? हमको भी सफाई से सुनने का मिलता है। इसके इलावा माननीय सदस्य ने भी हिन्दी में प्रस्ताव रखा है।

श्री कल्याण चन्द (उत्तर प्रदेश) : कौन जवाब नहीं है हिन्दी में जवाब दे।

श्री रबी राय : हम लोग अंग्रेजी नहीं जानते इसलिए हिन्दी में जवाब होना चाहिए। क्या बान करने है।

MR. CHAIRMAN : Please keep quiet. Let the hon. Minister, who has started it, finish it.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI CHANDRAJIT YADAV) : श्रीमन्, मैं दूसरे सदन में था क्योंकि मेरा वहाँ पर सवाल आया हुआ था इसलिए यहाँ पहुँचने में देर हो गई। Sir, in the first quarter of this financial year, difficulties were anticipated in the movement of coking coal as of other raw materials as a result of the strike in the Railways. Suitable adjustments in the production plans of the steel plants were made taking this into account in order to conserve the stocks of coal. As a result, a total stock of 288,000 tonnes of coal in all the plants was built up by the 1st of July. Production of steel was increased thereafter, but the stocks of coal were also maintained round about this level till September-October as a result of satisfactory position of supply. There was a setback in supply in the month of October, as a result of which the stocks fell in November. The supply in November was slightly less than the requirements at the current level of production. However, following a major accident on the 7th of December, at Chandil in the South-Eastern Railways, the movement of coking coal to Bhilai got reduced for two days and, as a result, the stocks in Bhilai have gone down on the 10th of December to 32,000 tonnes or a little more than three days requirements. I understand, however, that the lines have been cleared and that normal supply to Bhilai has started again. It is hoped that the stocks in Bhilai will be built up in the next few days.

2. I have had detailed discussions with my colleague the Minister of Energy in regard to supply of coking coal to the steel plants, and necessary steps for coordination are being taken to see that the supply is kept up at a satisfactory level. My department and the Ministries of Energy and Railways are working in close liaison with a view to maintaining adequate and steady supplies of coking coal to all the steel plants. I would like to assure the

[Shri Chandrajit Yadav]

House that the situation is constantly under watch and no effort will be spared to see that the supply of coking coal to the steel plants is adequate and satisfactory.

[श्री उपसभापति पीठासीन हुए ।]

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उप-सभापति जी, पहले तो मैं यह व्यवस्था चाहूंगा कि जब मंत्री जी हिन्दी अच्छी तरह से जानते हैं तो वे अंग्रेजी में क्यों बोले। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर मंत्री जी में हिन्दी में प्रश्न किया जाये और वे हिन्दी न समझे तो वे अंग्रेजी में ही बोले, लेकिन जब हिन्दी भाषा मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर जानबूझ कर अंग्रेजी में बोलें, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर वे हिन्दी में बोलते तो जो मेम्बर हिन्दी ही जानते हैं उन्हें इस बारे में काफी सुविधा हो जाती।

श्री उप सभापति : जब आप प्रश्न करेंगे तो वे हिन्दी में ही जवाब देंगे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मंत्री जी का हिन्दी में ही जवाब देना चाहिये था।

श्री उप सभापति : अब आप हिन्दी में पूछिये।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उप-सभापति जी, मंत्री जी ने अभी जो बयान दिया है उसमें उन्होंने यह आशा व्यक्त की है कि भविष्य में स्थिति में सुधार होगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि कल दो दिन जितने भी स्टील के कारखाने थे उनके मैनेजरों की जो मीटिंग हुई थी और 1974-75 के लिए स्टील का जो लक्ष्य 50.44 मिलियन टन का रखा था, जिससे से पिछले आठ महीनों में केवल 3.12 मिलियन टन ही स्टील पैदा हो सका है, और बाकी चार महीने जो बचे हैं, क्या इनमें पूरे साल का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा? क्योंकि वर्तमान स्थिति में जो कोयले की स्थिति है, उसके आधार पर क्या उनका यह लक्ष्य पूरा हो जायेगा? यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि विशेष तौर पर उम स्थिति के अन्दर जबकि अगले मार्च तक 34,325 मिलियन टन कोयले की जरूरत होगी और कोयले की प्रति दिन सप्लाई 32,400 मिलियन टन ही होगा। पिछले 9 दिसम्बर तक कोयले की सप्लाई केवल 29,800 मिलियन टन प्रति दिन रहा है। जिस प्रकार से कोयला मिल रहा है और जिस प्रकार से कोयले की स्थिति दिखाई देती है और जैसाकि मंत्री महोदय ने अभी कहा कि कोयले के खान श्रमिकों ने हड़ताल की धमकी दे दी थी और उसके कारण कोयले की सप्लाई में कमी पैदा हो गई। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कोयले वालों की हड़ताल तो हुई नहीं और अब तो सरकार का उनको

मार्थ समझौता हो गया है, लेकिन पिछले तीन चार महीनों के अन्दर जिस तरह से कोयले की सप्लाई रही है, जिस तरह से पर डे कोयले की सप्लाई में कमी होती जा रही है, इस नाते सरकार ने जो स्टील का लक्ष्य रखा था, क्या वह लक्ष्य पूरा हो जाएगा, यह बात मुझे दिखाई नहीं देती है। मुझे यह बात नहीं दिखाई दे रही है कि इस समय जो कोयले की कमी हो गई है वह किस प्रकार से पूरी होगी और जो स्टील के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, वह किस तरह से पूरा किया जायेगा?

श्रीमन्, इस सारे कालिग एग्जेशन के अन्दर कोई दाँप हो सकता है तो वह कोयले मंत्रालय का हो सकता है और कोयला मंत्रालय की ओर से यहां पर कोई भी मौजूद नहीं है जो कि मंत्री महोदय को इस बारे में किसी बात की जानकारी दे सके। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है वह यह है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे से 90 प्रतिशत कोयला इन स्टील प्लांटों को पहुंचाया जाता है और 90 प्रतिशत कच्चा माल भी इसी रेलवे के द्वारा पहुंचाया जाता है। लेकिन साउथ ईस्टर्न रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा है और ईस्टर्न रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा है उनके वेगनों में प्रति दिन कोयला भर के ले जाया जाता है और वेगनों की सप्लाई में कोई कमी नहीं है और रेलवे मंत्रालय को इस बारे में दोष नहीं दिया जा सकता है कि वह रेलवे वेगन सप्लाई नहीं कर रहा है। सितम्बर मास में 2834 वेगन प्रति दिन उठे, अक्टूबर में 2717 और दिसम्बर में 2507 डिब्बों में कोयला लादा गया। इसका मतलब यह है कि जितना रोजाना डिब्बों में कोयला भरा जाता था उसके एवरेज में कमी होती जा रही है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि जितना कोयला स्टील मिलों को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। इस दृष्टि से अगर हम रेलवे को दोषी ठहराए तो यह उचित नहीं होगा क्योंकि उनका कहना है कि हम तो वेगन बराबर देते जा रहे हैं। अगर वेगनों की कमी का सवाल नहीं है तो कोयले के खानों में इस समय जो व्यवस्था है, कोयले की जो वाशरीज है, वहां पर इस समय जो श्रमिकों की स्थिति है, देखभाल की जो व्यवस्था है, जिसके कारण कोयले के उत्पादन में कमी आ रही है, जितना कोयला हमको चाहिए उतना हम नहीं ले पा रहे हैं, जिस तरह की कठिनाई साउथ ईस्टर्न रेलवे वाले और ईस्टर्न रेलवे वाले महसूस कर रहे हैं उसी तरह की स्थिति बाकी रेलवे में भी आने वाली है।

इसलिए स्टील प्लान्ट्स की जो स्थिति मैंने बताई है और कोयले की सप्लाई की जो स्थिति है—दोनों प्रकार की दिककत आपको आने वाली है। आपने केवल भिलाई की बात बताई है। यही स्थिति दुर्गापुर की है। हरकेला और बोकारो स्टील मिल के लिए भी कोयले की कमी अनुभव हो रही होगी। उस कमी को दूर करने के लिए

आप किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे यह मैं जानना चाहूंगा। कोयले का हमारा लक्ष्य है 93 मिलियन टन के उत्पादन का जबकि हमारी एक्सपेक्शन है 88 मिलियन टन। इस साल कोयले का उत्पादन भी कम हो रहा है। जिस प्रकार का कोल आपको मिला रहा है उसके सम्बन्ध में भिलाई वालों की भी शिकायत है, बोकारो वालों की भी शिकायत है और दुर्गापुर वालों की भी शिकायत है कि कोयले का एश-कन्टेन्ट अब बढ़ता जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि यह किस कारण से हो रहा है? क्या नेशनलाइजेशन के बाद ही यह दिक्कत पैदा हुई है या उसके पहले भी इसकी दिक्कत थी? नेशनलाइजेशन के बाद स्टील मिलज को मिलने वाले कोयले की क्वालिटी में जो डिटेरियोरेशन हुआ है क्या उसका प्रभाव स्टील के निर्माण पर नहीं पड़ रहा है? कोयले में एश कन्टेन्ट ज्यादा होने का प्रभाव स्टील के निर्माण पर पड़ रहा है। इस कमी को दूर करने की दृष्टि से आप अपनी ओर से क्या व्यवस्था कर रहे हैं? उर्जा मंत्रालय में आपका किस प्रकार का तालमेल है? स्टील मिलज को अच्छा और बढ़िया कोयला प्राप्त हो सके इस दृष्टि से आपने कौन सी व्यवस्था की है?

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। उन्होंने बहुत विस्तार से समस्याओं के ऊपर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने यह कहा कि मैंने केवल भिलाई के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दिया है और सूचना दी है। चूंकि माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केवल भिलाई के सम्बन्ध में था इस लिये जो सूचना मैंने दी है वह मुख्य रूप से भिलाई के सम्बन्ध में है, लेकिन कोयले की सलाई की पूरी स्थिति क्या है उसका भी विवरण मैंने अपने वक्तव्य में आपको दिया है।

श्रीमन् जहां तक माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि 5.4 मिलियन टन का लक्ष्य हमारा बनाने का हमने निर्धारित किया है, पिछले 8 महीनों का जो हमारा लक्ष्य रहा है उसको हमने शत प्रतिशत पूरा किया है। जो शेष 4 महीने हैं उनमें आम तौर से यह होता है कि तीन महीनों में इस्पात का उत्पादन ज्यादा अच्छा होता है। अभी इस्पात कारखानों के प्रबन्धकों की बैठक हुई थी। उसमें सभी ने हमको इस बात का विश्वास दिलाया कि सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ताकि हम अपने उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें इस साल। इस साल जितना उत्पादन हुआ है वह पिछले साल के उत्पादन से काफी अच्छा और बेहतर हुआ है।

श्रीमन्, जहां तक कोयले का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने उसके लिये उर्जा मंत्रालय को दोषी बताया है और कहा है कि राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले का उत्पादन गिरा है और इस लिये यह स्थिति पैदा हो रही है। यह बात बिल्कुल

सही नहीं है। ऊर्जा मंत्रालय जितना सम्भव है कोयले के उत्पादन के प्रयास कर रहा है। जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा, मैंने अपने महयोगी ऊर्जा मंत्री से विचार विमर्श किया, अधिकारियों से विचार विमर्श किया, बी० सी० सी० एल० और सी० एम० ए० जो कोयले की देखभाल करते हैं और उनके उत्पादन का देखते हैं उनके अधिकारियों से बात की। हम सारे ऐसे कदम ल रहे हैं ताकि कोयले की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके।

जहां तक राष्ट्रीयकरण का बात है, 70-71 में कोयले का उत्पादन हुआ था 72.95 मिलियन टन। 1973-74 में बढ़कर वह 77.87 मिलियन टन हो गया, 5 मिलियन टन में ज्यादा उत्पादन हुआ है। इस लिये यह कहना कि राष्ट्रीयकरण के बाद उत्पादन गिरा है, सही नहीं है।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है वह सही है कि हमको इस्पात के उत्पादन के लिए कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में कोकिंग कोल, तान-कोकिंग कोल के मुकाबले में कम है। कोकिंग कोल का उत्पादन पिछले दिनों में घटा है। हम इसलिये अब सारे ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि कोकिंग कोल के उत्पादन को किसी तरह से बढ़ाये। उसके लिए जो आवश्यक कदम लेने हैं वे ले रहे हैं। अभी तक इस साल लोहे के उत्पादन पर कोयले की कमी की वजह से कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन यह बात सही है कि जितना स्टाक हमको चाहिए, जितने दिनों का रिजर्व होना चाहिए उसको देखते हुए स्टाक कम है। हम इस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस स्टाक को हम बना कर रख सकें इसलिये जितने हमारे कदम हैं वह उठाये जा रहे हैं। यही नहीं कि हमने उर्जा मंत्रालय के साथ ही बात की, रेलवे मंत्रालय, उर्जा मंत्रालय और हमारे मंत्रालय की लगाना मीटिंग हुई है और सब तरह के कदम उठाये गये हैं। किसी एक मंत्रालय का दोष देने का मवाल नहीं है। जहां तक आपने ऐश कटेड की बात कही वह कोल में बड़ा है और उसका मुख्य कारण यह है कि जितनी ज्यादा गहराई में हम कोयले की खेदाई कर रहे हैं उतनी ही कोयले की क्वालिटी निम्न स्तर की मिलती जा रही है और उसकी वजह में कुछ ऐश कटेड बढ़ा है। हमने इस बात की सावधानी बरती है कि हमारी वाशरीज में कोयले की अच्छी धुलाई हो सके और उसके लिये जो आवश्यक कदम हैं वह उठाए जा रहे हैं जरूरी इन्विस्टमेंट हम ने मगाये है या संगठन का जो मतकता बर्तनी चाहिए वह हम बरत रहे हैं और उसके लिये कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसलिये मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा है, यह बात सही है कि इस वक्त कोयले का स्टाक हमारा कम है, लेकिन हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं। इस वक्त जो कमी हो गई उसका कारण मैंने

[श्री चन्द्रजीत यादव]

बतलाया कि दुर्भाग्य में एक रेलवे की दुर्घटना हो गई और उसकी वजह से तीन दिन तक जितना कोयला आता था वह नहीं आ सका और उसकी वजह से स्टॉक कम हो गया है। हमने रेलवे मंत्रालय से दरखवास्त की है और ऊर्जा मंत्रालय में भी कहा है कि भिलाई के कोयले में कमी न होने पाये इसलिये यह देखे कि इसको हम ज्यादा कोयला दे सकें ताकि किसी तरह से भी उत्पादन में कमी न आये।

SHRI HARSH DEO MALAVIYA (Uttar Pradesh) : Sir, our hon. Minister has very rightly referred to the increase in the ash content of coal which is being used at Bhilai and pointed out that this is affecting the production of coke. Now, I would like to ask the hon. Minister to tell us the percentage of increase in the ash content of coal. I understand, it has gone up from 17 per cent to 24 per cent. But I do not know exactly. And how is this increase in the ash content of coal going to affect the production in the coke oven battery? To what extent will it affect because it is a big problem not only with the Bhilai plant but with other steel plants also. Then, Sir, I would like to know about the sources of supply of coal. You have pointed out that you instructed them to increase the supply, etc. I believe, Bhilai steel plant has certain captive mines. What is the number of captive mines which Bhilai has for the supply of coal? In view of the problem which always comes up about the supply of coal, will you consider some proposal to increase the number of your captive mines? Now the mines are nationalised. Would you not consider it more feasible to have, in co-operation with the Energy Ministry, some more captive mines under your possession so that you may be at least free from the usual red tapism, etc.? To what extent this ash content increase has affected your coke production per coke oven battery?

Then, Sir, very rightly, Shri Mathur and also our Minister referred to the washeries. I understand that our coal washeries are not up to the requisite standard. They are in use for a number of years. They are not so modern and up-to-date. And I was told that if we can wash our coal better, we can have better quality of coal for the coke oven batteries. Sir, washing of coal is a very vital question. So, what are you doing to improve your coal washing? I understand that the M. A. M. C., the public sector Corporation, is in a position to make the coal washeries.

Is the Government seized of the matter? I believe the MAMC is under the Steel Ministry—I do not know exactly. What are you doing? Have you given any specific instructions to raise the quality of their coal washing by importing technical know-how and anything else you may think best? What are the possibilities of our making our own coke oven batteries? How many coke oven batteries we are able to make ourselves and for how many have we to depend on imports? Then, how are the industrial relations? I believe industrial relations in Bhilai are in a good state and I think proper industrial relations in the steel plant at Bhilai will also improve the production of coke. I would like to have your views on this.

My last two questions will be: How does the defect in the ash content of coal affect your by-products? Because, Bhilai is making a large number of by-products which are very useful. For example, there is ammonium sulphate, there are five categories under the benzol products and more than a dozen of tar products. How does this affect your by-products for which Bhilai is famous and for which you also get a lot of money? There are very many major wastes which you also make use of like steel scrap, etc. and how are these major wastes affected by the ash content of the coal? I would like to know what you want to do about it.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : Sir, it is a fact, as I said earlier, that the ash content has increased. Now, it differs from plant to plant but, on the whole, it has been noticed that during the last few months the ash content has increased from 0.5% to 3 to 4 per cent in some plants. For example, in Bhilai, in comparison to last year it is only 0.5%. In Rourkela it is 1.0%. In Durgapur it is 2.09%. But we have received continuous complaints that the ash content is growing and, as I said earlier, all possible steps are being taken. The hon. Member has asked whether because of ill-equipped washeries and lack of proper equipment, the ash content is growing. Actually we are facing a new problem. As I said earlier, as we are having deeper mining—we are going much deeper—the quality is deteriorating. It is a fact that at present some of the washeries are not adequate and we have placed orders. We have to do some balancing in the equipment so that we may wash the coal in a better way. This care has been taken and orders have been

placed and I will see that we are able to meet this situation. The other question the hon. Member has asked is whether we will rely upon our captive coal mines. Excepting TISCO and IISCO which have some captive coal mines, the other steel plants do not have captive coal mines. Bhilai has no captive coal mines. This is a suggestion—whether the steel plants would like to have captive coal mines just as they have captive iron ore mines—and the suggestion can be considered.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA : You have some, I believe.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : I said that Bhilai has none. TISCO and IISCO have captive coal mines but Bhilai has not. We have captive iron ore mines—not coal mines.

So far as industrial relations in Bhilai are concerned, Sir, as the hon. Member himself has admitted, it is true that we have very good industrial relations there and there has been no trouble so far as Bhilai is concerned. For that matter, really speaking, for the last six months there has been no major industrial trouble in any of the steel plants and we are satisfied with our industrial relations.

It is a fact that the ash content, when it increases, does affect the coke oven batteries, it affects the blast furnaces and it also affects the production of steel and, therefore, we are taking all necessary steps so that we can control the increase in ash content.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA : I asked whether the saleable steel is affected.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : Sir, as I said, actually when the batteries and the blast furnace are affected, the saleable production also gets affected. The by-products are not directly affected.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA : Have you instructed your M. A. M. C. to have better quality washeries ? Are you importing technical know-how for that ?

SHRI CHANDRAJIT YADAV : There is no question of importing any technical know-how. We have got all the technical know-how. The two main suppliers, B.C.C.L., and C.M.A. are taking all the necessary care. As I told you, we are facing a new situation and a certain balancing is required.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Dr. Mathew Kurian.

DR. K. MATHEW KURIAN (Kerala) : The statement of the hon. Minister is quite unconvincing because instead of accepting the seriousness of the situation, he has tried to bring in the problems of railway strike and so on which, according to my mind, are not the core sector problems. As reported in the Times of India and also admitted by the Minister today, the coking coal stock with the Bhilai Steel Plant was only for 3 to 4 days. I would like to know from the hon. Minister whether it is not a fact that this is not a temporary shortage. This shortage is country-wide and the present deposits would last only for about 60 years according to the present estimates. Therefore, there is an absolute potential shortage apart from this temporary problem of railway wagons and so on. I would like to know whether it is true.

Secondly, I would like to know whether the Union Government has been considering the import of coking coal to maintain the present production level in all the steel plants. This is reported in the Times of India, New Delhi, dated 11th December. I would like to know whether this is true. The third question is regarding the alternatives to coking coal. There have been various discussions and certain technical innovations regarding alternatives to coking coal. For instance, according to one report, it is said that there is a significant innovation suggested by the experts from the Soviet Union who have been helping the Bhilai Steel Plant. It is regarding the introduction of non-coking coal dust into blast furnace No. 2. They have stated that they can introduce the non-coking coal dust into blast furnace No. 2, by 1976. This seems to be a very significant breakthrough. I would like to know whether it is true and whether the Government is taking any concrete steps about this.

I would also like to know the results of the recent second meeting of the Indo-Soviet Commission in Moscow. I understand that this problem was discussed. I would like to know whether a realistic and time-bound programme for the rapid expansion of Bhilai Steel Plant to the 4 million stage is being implemented and what are the bottlenecks and difficulties in the way. Is it true that the Soviet Union has already promised to provide a technical project report about the innovation to in-

[Dr. K. Mathew Kurian]

introduce non-coking coal dust into the blast furnace, thereby conserving the limited resources of coking coal? I would also like to request the hon. Minister to indicate the overall Bhilai Steel Plant's expansion programme. Is it true that the Bhilai Steel Plant has exceeded the production target of 1008 thousand tonnes and has touched the production of 1046 thousand tonnes of saleable steel? Will the supply of coking coal be increased for Bhilai Steel Plant in view of the fact that they have exceeded the target?

They have exceeded the target. Therefore, this problem is equally important. In order to reach the target of the Bhilai Steel Plant—the steel plant has exceeded its target according to my information—naturally it requires more coking coal at present. Therefore, the significance of alternative sources of energy, may be non-coking coal dust and the technical innovation suggested by the Soviet team. I would like the hon. Minister to enlighten the House regarding the discussions at the second meeting of the Indo-Soviet Commission in Moscow and what steps are being taken to reach the 4 million tonnes target by 1979.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : Perhaps the hon. Member has not understood me properly. I did not put the blame on the railway strike. I said then we had apprehended that there might be difficulties and there might be shortage of raw materials. We took all possible measures. Really speaking then we were in a better position and we had much better stocks because necessary steps were taken to increase the stocks. Later on, the stocks have come down because of various factors and necessary steps are being taken. Now, Sir, about what the hon. Member said, I told him and the House earlier that it is a fact that in our country we do not have a very big reserve of coking coal. In regard to non-coking coal, fortunately we are one of the few countries which have good reserves. So far as coking coal is concerned, our reserves are not very good. The hon. Member himself has given information that according to the present assessment and surveys it is only enough for sixty years. But we cannot say so. In a vast country like ours surveys are made and new mines are found. According to today's assessment it is a fact that it may be adequate for the next sixty years. Therefore, a country like ours should take advantage of all new techniques and knowledge

available on this point and we would like to introduce non-coking coal dust also into the production of steel. The Soviet Union did make an experiment, but later on they did not carry it forward because they have no shortage of coking coal. So far as we are concerned, we have asked MECOM to do the necessary experiments. We are taking note if any other country has achieved any significant result on this score. If so, we would like to take advantage of the new technique, but it is still under study. It has not been developed. Our research is taking care of this aspect. As the hon. Member has said, Bhilai steel plant is one of our best plants. It has exceeded the production target this year and that is why we are a little concerned that because of the shortage of coking coal, production should not be affected. All possible steps are being taken. So far as the Bhilai expansion programme is concerned, there was some delay because of various factors. All necessary steps are now being taken and expansion is taking place as scheduled. We will see that the expansion programme is completed according to the new scheduling which we have been able to do.

DR. K. MATHEW KURIAN : The hon. Minister has not replied to two of my specific questions. One is the report which appeared in the Times of India regarding the import of coking coal—whether it is true or not. Secondly, may I know whether it is true that at the second meeting of the Indo-Soviet Commission meeting Moscow had offered to the Government of India the technique and know-how about how to use non-coking dust in the furnace by 1979?

SHRI CHANDRAJIT YADAV : So far as the first question is concerned, we are not planning to import coking coal at present. We feel we can meet the requirements from our own country. There is no proposal for importing coking coal. So far as his second question is concerned, I am not aware whether this question was raised in the Indo-Soviet Commission meeting, but as I have pointed out, we would like to take advantage of any technology, any knowledge, which will help us in using non-coking coal dust in the production of steel.

DR. K. MATHEW KURIAN : I have got here the statement, which appeared in the Patriot of 24th October, of the General Manager of the Bhilai Steel Plant, Mr. P. K. Ahuja.

According to him, at the recent second meeting of the Indo-Soviet Commission, "a significant innovation has been suggested by the Soviet side with regard to the introduction of non-coking coal dust into blast furnace No. 2 by 1976." This is the specific information given to the press by the General Manager of the Bhilai Steel Plant. Is not the hon. Minister aware of it?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He is not aware of it. If the General Manager says something and if he is not aware of it, what can he do ?

DR. K. MATHEW KURIAN : What about the flow of communication between the Minister and the General Manager?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He will find out.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : Put a separate question.

SHRI T. N. SINGH (Uttar Pradesh) : I have listened with a very great deal of attention to the statement from the Government side. I want to raise two or three points. If I have correctly heard him, he has stated that the production target is 5.4 million tonnes of finished steel or ingots.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : Saleable steel.

SHRI T. N. SINGH : That means seven million tonnes of ingot steel to give 5.4 million tonnes of finished steel or saleable steel. All our plants taken together— the major steel plants and also the mini-steel plants that have been set up—should have more than 10 million tonnes of ingot capacity. To achieve what you have targetted for means running the steel plants at only 70 per cent of their capacity and not 100 per cent. I think it is much lower. From whatever I know, I can say that taken together the steel plants are not working to more than 60 per cent capacity. My point is, if you put a lower target as against your actual need and then if you say that you have achieved the target, it is not good. And in a planned economy such a thing will defeat the very purpose, it is deluding ourselves. Therefore, I want this point to be clarified. My point is, are you achieving what you are expected to, or are you achieving what you are really equipped to produce? Thousands of crores have been spent. But we do not get

the result. And this thing has been going on for the last ten years. It is really very distressing. 'Target' is a very pliable term according to what I see from the Government side. I warn them that this kind of misleading the people is wrong.

Secondly, the steel plants should have a rule that they will have a minimum stock of so many days in respect of coal, iron ore, limestone, dolomite, etc. All that should be worked out and it should be seen that at no stage the minimum stock planned is reduced. It is because the shortage that is today attributed is due to some accident which blocked traffic for two days. Such accidents may occur always and if we do not take this into account and provide with such a stock, we will be failing in our duty. What I want to make out is that the policy of having stores for a certain number of days has not been implemented. It has been worked out but not implemented.

And never should the stocks be allowed to come down below 10-15 days requirement. That is what I feel. So it is not a measure of satisfaction.

Again, we should not mislead the House because the situation is not really alarming in that sense. It has been bad. The policy has been bad. The implementation has been bad. The programming of the Government has been defective all these years.

Then there is the question of ash content. Various methods have been suggested. One is washeries. That is one of the methods. We shall, perhaps, have more washeries. But it is also a fact that our washeries are not running to capacity. This element of not running to capacity, not getting full value of the money invested is continuing.

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra) : Bad maintenance.

SHRI T. N. SINGH : Mr. Goray is perfectly right when he says that there is bad maintenance. Even Bhilai suffers from bad maintenance to the extent that there was an accident. In the coking oven pipes there was extra accumulation of tar blocking the functioning of the steel plant. And that is what is happening in Rourkela as also in the Durgapur steel plant. These plants have never worked to any appreciable capacity. So maintenance has been very bad. The moment for-

[Shri T. N. Singh]

ging is done there is some difficulty. There is always a very large amount of reduction in production. So this is to be taken care of.

Apart from the problem of washeries not being properly maintained, there is also the problem of proper blending. We know that we have got coking coal, semi coking coal, very light coking coal and what was all right as blending policy ten years ago is not correct today. As the Minister rightly pointed out, as we go down deeper in our coal mines' lower strata there is more of ash content. This is known for the last 15-20 years. After all, in a planned economy we look forward to the anticipated problems and find out the solutions for them. Therefore, in this particular case this was known. So we should have taken action well in advance to meet the problem of higher ash content. My contention is that proper step has not been taken. Not only that, there is complete lack of thinking in the Steel Ministry in this regard. That is the charge I make.

Then in regard to non-coking coal being converted into a kind of coking coal from ash or from dust I agree with what my honourable colleague Dr. Kurian has said. I think more than ten years ago the Fuel Research Institute or the F. R. I. were carrying on experiments in regard to what is called making use of non-coking coal for coking purposes, for steel manufacturing purposes. That was ten years ago. Our tragedy is that when ideas come we never pursue them properly. This is not a Russian idea. It is already there. But no progress has been made. Similarly there was a process developed in the F. R. I. for manufacturing fertilisers from coal with 14 per cent nitrogen as against 20 per cent. In the ammonium sulphate and other fertilisers. This has been there for the last fifteen years. But nothing has been done. My purpose in referring to this was that we have got ideas, but we do not process them, we do not pursue them. And then suddenly somebody from outside comes and shows us something and we say that it is a very brilliant idea. This kind of inferiority complex must go.

As I said there will have to be a different norm for planning of coal. Then our washeries have to run to capacity. You go on setting up new plants, I do not know how much time the washeries take. Do it by all means, but see to it that the capacity that you have is fully utilised. That is not being

done. I know it. It is no use the Minister trying to refute that statement of mine. Fourthly, if the picture of coking coal is so gloomy, what are we going to do regarding our steel plants? We are planning in a big way. There will be four or five additional steel plants. That is what I read in the papers. And the capacity of the existing plants will be doubled or trebled. All these schemes are going on. We know we have got very little coking coal. Shall we not apply our minds, shall not our technicians and scientists apply their minds, before actually the problems overtake us? We have to do it because to depend on imported coking coal will be a very difficult proposition. Probably it will be unbearable for our economy. (*Time-bell rings*) so, I say, this has also to be looked into. Our steel plants themselves have to be so regulated as to be in consonance with the coking coal that we have, with what we can do in the shape of technological innovations and improvement and with our requirements of various kinds of raw materials and technology in this country.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : Sir, the hon. Member has been Minister of steel and, therefore, he has sufficient knowledge of the problems which our steel industry face in this country. I am glad that he has pointed out certain problems.

SHRI T. N. SINGH : Not only problems. I have suggested certain solutions also.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : I agree with the hon. Member that we should not be satisfied only with achieving the target that we fix for every year. The results of these steel mills should be seen in how they utilise their installed capacity. I also agree with him that today we are not able to achieve the desirable capacity of the steel mills. I personally feel that in our country the steel mills should not produce less than 80 per cent of the capacity. In Japan they produce 90 per cent of the capacity.

SHRI T. N. SINGH : 105 per cent.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : I am myself admitting that. But I am also saying that we have taken all care. In our General Managers' meeting, I made this point very clear, that it is not enough that we fix a target and we achieve that target. That is not a very big credit for us. We should try our best and see that we make the maximum use of our

installed capacity. But, as the hon. Member knows, there are various constraints. There are outside constraints. These steel plants do not function independently. Coal has to be supplied, electricity has to be supplied, the railways have to work, refractories have to be provided. But as Government we should take all care to see that proper co-ordination is achieved. In this respect, all possible measures are being taken. I will not accept the statement that the planning has been bad, that we have done bad planning and programming. The question is...

SHRI T. N. SINGH : What I said was, in view of these constraints, the future planning of steel has not to be on an *ad hoc* basis. You are planning steel plants in so many places. That should be done only in the light of our resources and experience in the past.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : Sir, I can only assure the hon. Member that when we are planning certain steel mills for the future, we are also taking all possible things into consideration. We know that our requirements in future will increase. We are a developing country. We have to produce steel in our own country. We cannot go on importing steel from outside.

We will have to pay very heavy bills. Therefore, new steel mills will have to come in this country. The picture is not so gloomy as the hon. Member tries to paint it here...

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : यद्वा तो 'स्लूमी' कुछ है ही नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव : 'स्लूमी' तो कुछ है, लेकिन कुछ पहलू रोशन भी है। सब 'स्लूमी' ही नहीं है। I agree with the hon. Member when he says that we should have proper stock of coal in the steel plant. I express my concern that in spite of the fact that we have planned like that and in spite of our best efforts we have not been able to build up very good stocks. I agree that the steel mill should have not less than 10 days stock of coal. All possible steps are being taken. I also agree that this kind of accident does obstruct the work of the steel plant in Bhilai. It is not that it is not foreseen. Before the accident took place we were considering : suppose this happens and then what will happen to the mill with a low stock? Then our plant will be in difficulty. Therefore, the minimum stock should be not less than 10 days, stock. We are tak-

ing this into account so that in future we will have proper stock of these inputs. Then difficulties may not arise. Shri Goray mentioned about bad maintenance.

SHRI N. G. GORAY : I was told by an Engineer in Bhilai that the maintenance is so bad that a machine which ought to serve us for nearly 25 years will serve only five years because of bad maintenance.

SHRI T. N. SINGH : Improper maintenance has pursued our steel production all these years. I am going to Bhilai and I will check up and then tell the House what we feel about it.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : I will be very glad if the hon. Member will help me in this. It is a fact that maintenance is a very important aspect, particularly in steel plants, and there has been certain slackness on this issue. But all the possible cares have been taken and we have instructed our General Managers of steel plants that they should personally pay attention to the maintenance aspect of the steel plants so that the plants do not suffer because of bad maintenance...

SHRI N. H. KUMBHARE (Maharashtra) : Why was that aspect neglected in the past?

SHRI CHANDRAJIT YADAV : The hon. Member should appreciate what I say. Instead, why are you trying to jump at it?

So far as blending of coal is concerned, it is correct that we have prime coking coal, medium coking coal and blendable coking coal. A certain percentage has been fixed for that. According to our requirements, we have sometimes medium coking coal and sometimes there are difficulties for blendable coking coal. According to their requirements, the plants have been trying to adjust the blending of the coal. It is not that we have not taken this aspect into consideration. We have considered that aspect. As I said earlier, we are aware that in this country at a later stage in future we may find difficulties so far as coking coal is concerned. Therefore we will take advantage of any technology, whether it comes from Soviet Union or any other country for that purpose, which will help us in steel production with introduction of non-coking coal. That I can assure the hon. Members.

श्री रबी राय : डिप्टी चैयरमैन माहव, चन्द्रजीत यादव जी इस मंत्रालय के नये मंत्री बने हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वह ऐसे मंत्रालय के उत्तराधिकारी बने हैं जिसका कोई सुनाम नहीं है। इसलिये उनको ज्यादा अग्रमूर्खी बनकर इस बारे में जवाब देना चाहिए।

अभी ये मान चुके हैं कि अगले 4 महीने में उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति करने के लिये है। क्या यह सही है कि दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रूरकेला और दुर्गापुर की शार्टफाल भिलाई के जरिये पूर्ति होगी? जब यह सही है तो अगले 4 महीने के अन्दर इनको 34325 टन कोकिंग कोल की जरूरत है प्रति दिन जब कि इस महीने के 9वें दिन में अभी 29800 टन तक आया है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यह जो शार्टफाल है कोकिंग कोल में उसकी पूर्ति करने के लिये वह क्या व्यवस्था कर रहे हैं।

अभी माधुर माहव के प्रश्न का आपने जवाब दिया। राष्ट्रीयकरण जब समाजीकरण में परिवर्तन होता है तो कुछ समाज की भलाई के लिए होता है और राष्ट्रीयकरण जब सरकारीकरण हो जाता है तो फिर नौकरशाह, मुट्ठी भर लोगों के लिये होता है। यह फर्क शायद चन्द्रजीत जी करेंगे। सी० एम० ए० और भेल में दोनों पब्लिक अंडरटेकिंग है। डिप्टी चैयरमैन माहव, आप ताज्जुब करेंगे मालवीय माहव इसको मान चुके थे पिछले सत्र में कि सी० एम० ए० का दफ्तर एक 5 स्टार होटल में है। उसी तरह आप देखेंगे कि किस तरह में फिजूल खर्चा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि चन्द्रजीत यादव जी छानबीन करें। मान लीजिए कि यह स्टील मैनेजर का खुद का प्लान है। मैं इसलिये कहना चाहता हूँ कि सरकारीकरण जिसका मैंने जिक्र किया कि सरकारीकरण होने के बाद फिजूल खर्चों में ज्यादा रुपया बरबाद होता है और उत्पादन का आधुनिकीकरण करने के लिए जो सोच होना चाहिए वह नहीं होता है। क्या यह सही नहीं है कि बावजूद इसके कि एक जर्मन इंजीनियर ने एक किताब लिखकर दी कि रूरकेला का कैसा मेंटेनेंस हो। इस लिये कि उस किताब के ऊपर काम नहीं हुआ, रूरकेला की स्टील फैक्टरी का रूप गिर गया और उसमें करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि जो इंडिजनस फैक्टरीज है वह रिफ्रेक्टरीज की जरूरत को नहीं दे पा रहे हैं? क्या यह सही है कि विदेशों से रिफ्रेक्टरीज आयात करने की सोच रहे हैं और जो सप्लाय वार्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में कमी हो रही है।

फिर भिलाई के बारे में पहले भी मैं कह चुका हूँ और सदन में यह बात आ चुकी है कि मोवियत एम्बेसी के इकानामिक काउंसिल ने उनको खुद शिकायत की थी कि जिस तरह में भारत सरकार को उनके साथ सहयोग करना चाहिए जिस रूसी कोलाबोरेशन से बोकांगी, भिलाई में काम होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। मोवियत काउंसिल की शिकायत

बरकरार है या सरकार ने क्या कार्यवाही की है, आगे चलकर इस शिकायत पर आप क्या कर रहे हैं?

अन्त में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो जनरल मैनेजर हैं उनके साथ इनकी बैठक हुई थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये कोई काम देने है कि इस तरह की कंपैसिटी के अनुसार काम करिये। लक्ष्य की पूर्ति जब नहीं होती है तो मंत्री महोदय की जिम्मेदारी तो पार्लियामेंट के प्रति है, लेकिन जो जनरल मैनेजर हैं उनकी गलती से यदि उत्पादन नहीं हो रहा है तो उनके लिए वण्ड विधान के लिये कोई सोच है? इस पृष्ठभूमि में मैं जानना चाहता हूँ कि गेडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमिशन ने विभिन्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की गेफिशियेसी बढ़ाने के लिए जो सिफारिश की थी उसके कार्यान्वयन के बारे में चन्द्रजीत जी मंत्री बनने के बाद उसका अध्ययन किये हैं और उसके बारे में क्या पग उठाया है, यह सदन को बताएँ।

[P.M.]

कैबुल लेबर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास उनको परमानेंट लेबर में परिणत करने का कोई कार्यक्रम है?

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमान्, एक प्रश्न उठाया है माननीय सदस्य ने कि अगर दूसरे कारखाने जैसे दुर्गापुर और राउरकेला है अगर उसका उत्पादन अपने लक्ष्य के गुताबिक नहीं होगा तो क्या महज भिलाई से उस लक्ष्य की पूर्ति कर ली जाएगी? यह बात सही है कि अगर हमारे कारखाने भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे तो केवल एक कारखाने से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। यह माननीय सदस्य को जानकर खुशी होगी कि राउरकेला का जो कारखाना है इसका पिछले अप्रैल में लेकर मिनम्बर तक का जो लक्ष्य था उत्पादन का उसमें 3 लाख, 73 हजार, 900 टन इस्पान का उत्पादन करने का था और उत्पादन हुआ 3 लाख 76 हजार 732 टन। यह 100.3 प्रतिशत फुलफिलमेंट हुआ अपने लक्ष्य से। दुर्गापुर का भी पिछले सालों के मुकाबले इस साल उत्पादन बढ़ा है और हमें इस बात की खुशी है कि हालांकि यह कारखाना काफी बुरी स्थिति में रहा है, माननीय सदस्य जानते हैं कि दोनों सदनों में इसकी बड़ी चर्चा हुई है, लेकिन इस वर्ष उसका भी उत्पादन पहले के मुकाबले ज्यादा हुआ है। मैं समझता हूँ कि जिनने कारखाने हैं सब को निजी रूप से जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसका पूरा करना चाहिए क्योंकि एक कारखाना दूसरे कारखानों का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता। हमने जो मीटिंग की थी उसमें इस्पान का जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है उस लक्ष्य को हर कारखाने को पूरा करने की कोशिश करने के लिये कहा है।

आपका यह प्रश्न भी था कि यदि कोई अधिकारी, जो लक्ष्य निर्धारित होता है उसको पूरा नहीं करता है तो उसमें

कोई कमी होती है तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे उसको दंड दिया जा सके। मैं समझता हूँ इस बात को हम को देखना चाहिए। लाजमी तरीके से। जिन कारखानों में हमारा अरबों रुपया लगा हुआ है अगर उसमें हम अपना उत्पादन पूरा न करें तो हम को बाहर से आयात करने में उसके ऊपर काफी रुपया खर्च करना पड़ता है जब तक कि कोई ऐसा कारण न हो जो उसकी सीमा से बाहर हो और वह उत्पादन न कर सकता हो और अगर वह व्यक्तिगत रूप से लापरवाही करता है और उस पर उत्पादन पर अमर पड़ता है तो मैं समझता हूँ इस बात को देखना चाहिए। सरकार का उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए और हमें इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए।

जहां तक कोकिंग कोल के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस वक्त हम यह कर रहे हैं हमने जो बैठक बुलाई थी उसमें अधिकारी भी थे उनमें हमारी बातचीत हुई है और उसमें उनके प्रतिनिधि भी मौजूद थे, उनमें भी हमारी बातचीत हुई है। हम इस बात का कार्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं कि जितना कोकिंग कोल चाहिए हमारे स्टील प्लांट को, उतना देश में हम उत्पादन कर सकें। उसका एक तरीका हो सकता है कि हम कुछ नई खानें ले लें जिनके ऊपर काम किया जा सके। मेरा कहना है कि वह भी दो-तीन साल के बाद ही कोल देना शुरू करेगा। अब मवाल यह है कि इस वक्त जो हमारी कैपेसिटी है उसको कैसे पूरा करें? इस के लिये सगटन में ज्यादा वृद्धि करें और वाणरिज पानी के काम का ज्यादा अच्छी तरह से करें, जो मौजूदा कारखाने हैं उनके उत्पादन को बढ़ावे, यही काम हम कर सकते हैं। इसके लिये जो प्रयास हैं वे किये जा रहे हैं। दूसरे स्टील प्लांट है उनके जो कैपिटल माइन्ज है उनको भी कहा है कि उनकी अपना रुपया उसके ऊपर लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी जो जरूरत है उससे ज्यादा अपने कैपिटल माइन्ज को पूरा कर सकें ताकि जो हमारी कोकिंग कोल माइन्ज है उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें।

राष्ट्रीयकरण के बारे में आपने प्रश्न उठाया है। मैं आपसे सहमत हूँ कि राष्ट्रीयकरण अगर सरकारीकरण में या नौकर-शाही में परिवर्तित हो जाए तो राष्ट्रीयकरण अपने लक्ष्य में दूर हो जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इस लिये राष्ट्रीयकरण में केवल यह कि वह उद्योग सरकार के हाथ में आए, बल्कि मही मायनों में उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी है या उसमें सम्बन्धित जनता है या जनता के चुने हुए लोग हैं उनकी राय की कद्र की जाये। उन्हें अवसर दिया जाये अपनी राय से अवगत कराये का। मैं समझता हूँ कमजोरी हो सकती है इससे आप भी सहमत होंगे। आपने स्वागत किया कोयले के राष्ट्रीयकरण का। यह मानता हूँ कि जो कमजोरी हो उसको दूर किया जाए। मैं समझता हूँ जो कदम उठाया है सरकार ने राष्ट्रीयकरण का, उसको

कमजोर नहीं बनने देना चाहिए। यह एक अच्छा कदम है।

श्री राजनारायण : सरकार ने अष्टाचार को बढ़ाने का तो कोई जरिया नहीं बनाया है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : आपने राष्ट्रीयकरण की हिमायत की, इसका मैं स्वागत करना हूँ।

श्री राजनारायण : अन्य गन्धे मिनिस्टर्स में इनका स्टेटमेंट इम्प्रूव्ड है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीयकरण किया ही नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्री राजनारायण जी, विवाद के लिये यह अच्छा विषय है। प्रजातन्त्र में हम विचारों का स्वागत करने हैं और चाहते हैं कि उन पर वाद विवाद हो।

जहां तक रिफ्रेक्टरी का गवाल है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि रिफ्रेक्टरी की भी कमी है और हमारे इस्पात कारखाने इस बात की कोशिश में हैं कि उसके उत्पादन में वृद्धि हो। हमारे देश में रिफ्रेक्टरी की कमी कुछ तो इस लिए हो गई कि तामिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी में कट एप्लाई कर दिया जिसके परिणामस्वरूप जो ग-मेटिरियल कारखानों में जाना चाहिए था वह जा नहीं पाया। उड़ीसा सरकार ने ब्रिजली के मामले में कुछ प्रतिबन्ध इम्पोज कर दिये। जब मैं गउरकेला गया था तो मैंने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से इस बारे में बातचीत की थी और अब उन्होंने ब्रिजली रेस्टोर कर दी है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि रिफ्रेक्टरी के मामले में हमें कुछ माल इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। हमारी यह कोशिश है कि रिफ्रेक्टरी के मामले में हम आत्म निर्भर हो सकें, इस लिये हमारे जो कारखाने हैं, पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं, उनमें ही इनका उत्पादन हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज उसकी कठिनाई है और उसको दूर करने के लिये सभव कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री रबी राय : आप इसका आयात कब तक बन्द कर देंगे ?

श्री चन्द्रजीत यादव : जहां तक आयात का संबंध है, इस्पात एक ऐसी वस्तु है जिसमें दुनिया का कोई भी देश आत्म-निर्भर नहीं हो सकता है। कोई न कोई सामान किसी न किसी रूप में दूसरे देशों से मगाना पड़ता है। अगर हम रिफ्रेक्टरी की कमी अपने देश में पूरी कर लें तो दूसरी चीजें हमें दूसरे देशों से मगानी पड़ सकती है। आत्म-निर्भरता हम इस मायने में कह सकते हैं कि दूसरे देशों से माल मगाने के साथ साथ हम इस स्थिति में हो कि दूसरे देशों का भी माल भेज सकें। इसलिए मैंने कहा कि इस दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

इसके अलावा आपने सोवियत इकनोमिक एडवाइजरी कमिशन के बारे में कहा। इस वक़्त इस सबध में मैं यही कहूँगा कि सोवियत विशेषज्ञ हमारे यहाँ हैं और हमारे विशेषज्ञों और उनके बीच में बड़े मैत्रीपूर्ण संबध हैं और जो भी समस्या आती है उसको आपसी सहयोग से हल कर लिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई इस वक़्त नहीं है।

श्री राजनारायण : क्या इस सबध में कोई विवाद नहीं है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : इस वक़्त कोई विवाद नहीं है। यह जानकर आपको प्रसन्नता होनी चाहिए।

आपने कैंजुअल लेबर के बारे में भी कहा है। जितने भी हमारे इस्पात के कारखाने हैं उनमें हमारे स्थायी कर्मचारी काम करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कांटेक्ट लेबर द्वारा किये जाते हैं। इस बात की कोशिश की जा रही है कि कई कारखानों से कांटेक्ट लेबर को अलग किया जा सके और डिपार्टमेंटल प्ल बनाये जायें और कोऑपरेटिव सोसायटीज के जो कर्मचारी हैं उनसे यह काम लिया जाए। इस सबध में काम किया जा रहा है और इस वक़्त इसकी कोई समस्या नहीं है।

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA (Bihar) : Mr. Deputy Chairman, Sir, the question had a very limited scope. But because of Your kindness, you allowed the Members to discuss many aspects of the matter. We have very much profited by this exercise for which I am grateful to you. Sir, the hon. Minister has said that the officers of the Ministry of Energy and his Ministry have discussed about several matters. Personally, I would like to say that there should be a committee on plant basis of the officers of the Railway Ministry, the Energy Ministry and his Ministry besides the Apex Committee. There should be a committee like this for Rourkela, Bhilai and Durgapur Steel Plants and also very much for the Bokaro Steel Plant which is being built up.

By the middle of next year, we might have the good fortune, under the stewardship of Mr. Yadav, to see that steel is being manufactured at Bokaro. Sir, if this sort of a committee is not built up, then the apex committee will not be so useful as this committee. Besides, I would like to mention another thing. He requires electricity for which he talked to the Chief Minister and the Minister in charge of electricity in Orissa, etc. He requires so many things. In such matters,

a person like him should streamline the things and see that nothing is left to chance and that everything is organised properly and is happening automatically. Sir, he has been there only for a few weeks. But I have kept myself very much in touch with the Bokaro plant and other plants also. I keep in touch with some of the engineers who work there and in other places, and I write to them. This House will be happy to know that our Minister is moving in the matter. And, Sir, administration is more important than the coking coal, and there must be a harmony. If any officer, however big he may be, wants to create tension, wants to create a provincial feeling, wants to create a sort of group, he should see to it that such elements are eliminated, whatever be the consequences of that. I know he is both firm and mellow, and both are required to handle this human engineering in all these plants.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : Sir, I am grateful to the hon. Member. He has made certain suggestions, and he has expressed his confidence that I would be able with the co-operation of all my friends and colleagues and officers and workers to do the job that has been assigned to me. I would only like to say that so far as this suggestion that we should have a plantwise committee of Steel, Railways and Energy Ministries is concerned, this is a suggestion which we may consider. But we are really considering that we should have some kind of a committee where the officials of all the concerned Ministries are there, and all necessary steps to make available the inputs, the movement of inputs and other steps which are necessary would be taken care of.

Sir, I agree with the hon. Member that electricity is also a very important factor, and it has been affecting some production of our plants. And this question has been considered at various levels as to whether the steel plant should have a captive plant or whether we should have a national grid. It will be easier if the electricity is regularly supplied from the national grid. It will be cheaper and it will be better also. Therefore, these are the broader questions which are being considered. And I entirely agree with the hon. Member that the human part of these plants is very important. It is not only the machine which works, it is also the man behind the machine. He is very important. Therefore, proper co-ordination, cooperation, satisfaction of the workers, their sense of involvement, and their honest and

efficiency are very important factors, and these factors have to be taken care of. And I can only assure that so far as I am concerned, I hope and I am confident that I will be able to get the co-operation of all those who are concerned with the manufacture of steel, and will see that those people who are responsible for the production of steel also have a feeling of involvement and take it as their patriotic job to contribute in the production of steel.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Dr. Kurian. Special Mention.

**REFERENCE TO KERALA HIGH COURT
JUDGEMENT QUASHING THE
DISTRIBUTION POLICY FOR
IMPORTED CASHEWNUTS**

DR. MATHEW KURIAN (Kerala) : Sir, I wish to bring to the attention of the Government of India the very serious situation which has emerged as a result of the decision of a Single Bench of the Kerala High Court quashing the distribution policy for imported cashewnuts, which has so far been canalized through the Cashew Corporation of India, a subsidiary of the State Trading Corporation of India.

Sir, raw cashew as a raw material has always been in short supply, the major proportion of raw cashew being imported from African countries. Cashew factories in Kerala work only for about 7/8 months in a year and there is large-scale unemployment in the cashew industry belt. Sir, the industry has disintegrated into small cottage units called 'Kudiruppu', a factory which could be compared to the put out system during the early stages of the Industrial Revolution in Britain. Sir, in order to avoid the disintegration of the industry as a result of the continuous struggle of the working classes in cashew industry, the Government of India had agreed to canalize the import of raw cashewnuts through the Cashew Corporation of India to ensure the distribution of raw cashewnuts only to those processing units which conduct their operations in an organised manner and with at least minimum benefits given to the workers. Sir, in fact, the scheme has introduced a large measure of stability into the industry. The distribution of imported raw cashewnuts has been on the basis of strength of workers in

each establishment in order to prevent clandestine processing and non payment of legal wages to the working people, 95 per cent of whom are women.

Sir, I wish to bring to the attention of the Government the fact that the Kerala High Court quashed the distribution policy of imported raw materials mainly because of the inability and irresponsibility of the legal representatives of the Government of India in the Kerala High Court. I therefore request the Government to take into consideration the following three points.

(i) to initiate urgent appellate proceedings against a single Bench judgment :

(ii) to appoint a competent lawyer to handle the case ; and

(iii) to promulgate an Ordinance, if and when found necessary, re-enclosing the classification Nos. 21 and 22A of the entry in the public notice No. 183, ITC (PN)/73, New Delhi, dated 3-11-1973 inserted in Section 3 of the Import Trade Control Policy, i.e. Red Book Vol. I for April, 1973 to March 1974.

I once again request the Government to take up the matter urgently to ensure that the cashew industry is not allowed to be exploited by vested interests and allowed to be deteriorated and disintegrated into the hands of those flourishing in the past on the ill-gotten money through exploitation of the cashew workers.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

**The Code of Civil Procedure (Amendment)
Bill, 1974**

SECRETARY GENERAL : Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha :

"I am directed to inform Rajya Sabha that Lok Sabha, at its sitting held on the 11th December, 1974, has adopted the following motion extending the time for presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 1974.

MOTION

"That this House do extend upto the last day of the first week of the next Monsoon